

करेंट अफेयर्स : समसामयिकी विविध

रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें

■ बैंक दर - 5.40 प्रतिशत	■ सीआरआर - 4.0 प्रतिशत
■ रेपो दर - 5.15 प्रतिशत	■ एसएलआर - 18.25 प्रतिशत
■ रिवर्स रेपो दर - 4.90 प्रतिशत	■ एमएसएफ - 5.40 प्रतिशत
(12 फरवरी, 2020 की स्थिति)	

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

- नागरिकता संशोधन बिल/विधेयक (CAB), 2019 लोकसभा से 9 दिसम्बर, 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया।
- लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 311 तथा विपक्ष में 80 मत पड़े जबकि राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 105 मत पड़े।
- इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनो द्वारा पारित विधेयक 12 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन / हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है।
- इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, आफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल छह धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी।
- भारत में प्रवासियों को अब 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष रहने पर नागरिकता मिल जायेगी।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों को छूट दी गई है।
- नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे।
- अवैध प्रवासियों को विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत कारावास दिया जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है।
- सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था।
- संविधान के भाग-2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है।
- अबतक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार (1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019) संशोधन हो चुका है।
- अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है।
- किसी संशोधन बिल को पास करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 सदस्यों को वोटिंग करना आवश्यक है।
- नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वाँ संशोधन बिल है।
- नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाया गया है।

- CAA - Citizenship Amendment Act
- CAB - Citizenship Amendment Bill

भारत का नया मानचित्र

- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवम्बर, 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केन्द्रशासित प्रदेशों को दर्शाया गया है।
- यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है।
- लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश में दो जिले-कारगिल और लेह शामिल हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं जिसमें पाक अधिकृत दो जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल हैं।
- एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित, गिलगित वजारत, चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर में 14 जिले थे, जिन्हें वर्ष 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया था।
- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात् 26 जनवरी, 2020 से केन्द्रशासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है।

अयोध्या विवाद : सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- 30 सितम्बर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर-बराबर बाँटने का आदेश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- 9 नवम्बर, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या की विवादित भूमि के मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है, साथ ही मुस्लिम पक्ष (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) को अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है।
- कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया है, जो मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन की व्यवस्था देखेगा।
- कोर्ट ने इस मामले के पहले पक्षकार गोपाल सिंह विशारद को उनके निधन के 33 साल बाद पूजा करने का हक प्रदान किया है।
- उल्लेखनीय है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 से 18 अक्टूबर, 2019 तक 41 दिनों तक इस मामले पर प्रतिदिन सुनवाई की थी।
- इस संविधान पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस. ए. बोबडे (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश), डी. वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. ए. नजीर शामिल थे।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

- 31 अगस्त, 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।
- NRC के तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला के अनुसार, NRC की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए कुल 3,11,21,004 लोगों को योग्य पाया गया है जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं हैं। कुल 3,30,27,601 लोगों ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।
- अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च, 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं।
- अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals) के समक्ष अपील कर सकते हैं।
- असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से वर्ष 1979-85 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया था, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2019 में असम के लोक सेवा अधिकारी हितेश देव शर्मा NRC के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।

करतारपुर कॉरिडोर

- 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष में बनाए गए करतारपुर साहिब गलियारे के एकीकृत चेक पोस्ट का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवम्बर, 2019 को उद्घाटन कर तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया।
- करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत के गुरुदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक से शुरू होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला नरोवल में स्थित करतारपुर को जोड़ता है।
- ज्ञातव्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 26 नवम्बर, 2018 को बहुआयामी परियोजना करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी।
- उल्लेखनीय है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत से सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे।
- ज्ञातव्य है कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे और 1539 ई. में वहीं शरीर त्याग किया था।

मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019

- 31 जुलाई, 2019 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- इस विधेयक ने फरवरी, 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है। विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष (पति) को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी भरना पर सकता है।
- अदालत का फैसला होने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी। इस दौरान पति को गुजारा भत्ता देना होगा।
- ज्ञातव्य है कि तत्काल तीन तलाक को 'तलाक-ए-हिन्द' कहा जाता है।

योजनाएँ एवं उससे संबंधित राज्य

योजना	राज्य
हिमालय दर्शन योजना	उत्तराखंड
तेजस्विनी योजना	झारखंड
ई-ममता योजना	झारखंड
ई-लाइली योजना	मध्य प्रदेश
अमरूत योजना	गुजरात
स्वधरा गृह योजना	हरियाणा
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना	झारखंड
भामाशाह पशु बीमा योजना	राजस्थान
तीलू रौतेली पेंशन योजना	उत्तराखंड
मुख्यमंत्री राजश्री योजना	राजस्थान
महतारी जतन योजना	छत्तीसगढ़
अन्नपूर्णा रसोई योजना	राजस्थान
जय जवान आवास योजना	हरियाणा
सुपर 30 योजना	उत्तराखंड
शहीद ग्राम विकास योजना	झारखंड
दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना	उत्तराखंड
अंत्योदय आहार योजना	हरियाणा
अमा गांव, अमा विकास	ओडिशा
गोवर्धन योजना	हरियाणा
बेटी पढ़ाओं-बेटी बचाओं-बेटी खेलाओं	हरियाणा
ज्ञानोदय योजना	झारखंड
मथरू पूर्णा योजना	कर्नाटक
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	उत्तर प्रदेश
उजाला मित्र योजना	उत्तराखंड
डोरस्टेप डिलीवरी योजना	दिल्ली
अमृतम योजना	गुजरात
माझी कन्या भाग्यश्री योजना	महाराष्ट्र
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना	हरियाणा
एम सेहत योजना	उत्तर प्रदेश
इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला योजना	उत्तराखंड
बिल दो पुरस्कार जीतो योजना	हरियाणा
मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना (संबल)	मध्य प्रदेश
पौधागिरी अभियान	हरियाणा
भावांतर भरपाई योजना	हरियाणा
'चिराली सदा के लिए' योजना	राजस्थान
कौशल्य योजना	मध्य प्रदेश
अन्नपूर्णा दुग्ध योजना	राजस्थान
कैशलेस स्वास्थ्य योजना	असम
रूपश्री योजना	पश्चिम बंगाल
गोपाबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना	ओडिशा
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना	मध्य प्रदेश
रायथु बंधु योजना	तेलंगाना
शहरी गरीबों के लिए 'लैण्ड राइट स्कीम'	ओडिशा

■ पेड़-पौधों के साथ भाई-बहन का रिश्ता योजना	सिक्किम
■ निर्माण कुसुम योजना	ओडिशा
■ सौर जलनिधि योजना	ओडिशा
■ एक परिवार, एक नौकरी	सिक्किम
■ स्कूल फगदबा योजना	मणिपुर
■ जय किसान ऋण मुक्ति योजना	मध्य प्रदेश
■ जय किसान समृद्धि योजना	मध्य प्रदेश
■ कृषक बंधु योजना	पश्चिम बंगाल
■ रायथु भरोसा योजना	आंध्र प्रदेश
■ मुख्यमंत्री ऑनचल अमृत योजना	उत्तराखंड
■ वन-धन योजना	मध्य प्रदेश
■ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	बिहार
■ गुलाबी सारथी वाहन योजना	कर्नाटक
■ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना	झारखंड
■ सरबत सेहत बीमा योजना	पंजाब
■ 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट योजना	दिल्ली सरकार
■ नावोद्यम योजना	आंध्र प्रदेश
■ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	छत्तीसगढ़
■ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	उत्तर प्रदेश
■ नाडु-नेडु योजना	आंध्र प्रदेश
■ अरूंधति स्वर्ण योजना	असम सरकार
■ नेतन्ना नेस्तम योजना	आंध्र प्रदेश
■ जलसाथी कार्यक्रम	ओडिशा
■ अभिनन्दन योजना	असम
■ शिव भोजन योजना	महाराष्ट्र
■ अम्मा वोडी योजना	आंध्र प्रदेश
■ जनसेवक योजना	कर्नाटक
■ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना	हरियाणा

वर्ष 2014-19 में प्रारंभ हुए प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम

योजना	शुरूआत
■ पढ़े भारत बढ़े भारत योजना	27 अगस्त, 2014
■ प्रधानमंत्री जन-धन योजना	28 अगस्त, 2014
■ मेक इन इंडिया	25 सितम्बर, 2014
■ स्वच्छ भारत मिशन	2 अक्टूबर, 2014
■ सांसद आदर्श ग्राम योजना	11 अक्टूबर, 2014
■ मिशन इंद्र धनुष योजना	15 दिसम्बर, 2014
■ भारत नेट परियोजना	12 जनवरी, 2015
■ हृदय योजना (HRIDAY)	21 जनवरी, 2015
■ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	22 जनवरी, 2015
■ सुकन्या समृद्धि योजना	22 जनवरी, 2015
■ मुद्रा बैंक योजना	8 अप्रैल, 2015
■ उजाला योजना	1 मई, 2015
■ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	9 मई, 2015
■ अटल पेंशन योजना	9 मई, 2015

■ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना	9 मई, 2015
■ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	9 मई, 2015
■ प्रधानमंत्री आवास योजना	25 जून, 2015
■ अमरूत योजना (AMRUT)	25 जून, 2015
■ डिजिटल इंडिया	1 जुलाई, 2015
■ स्कूल इंडिया मिशन	15 जुलाई, 2015
■ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	15 जुलाई, 2015
■ प्रधानमंत्री जन औषधी परियोजना	21 जुलाई, 2015
■ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	25 जुलाई, 2015
■ भारतमाला परियोजना	31 जुलाई, 2015
■ नई मंजिल	8 अगस्त, 2015
■ सहज योजना	30 अगस्त, 2015
■ इम्प्रिण्ट इंडिया योजना	5 नवम्बर, 2015
■ स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	5 नवम्बर, 2015
■ उदय योजना (UDAY)	5 नवम्बर, 2015
■ वन रैंक-वन पेंशन योजना	7 नवम्बर, 2015
■ ज्ञान योजना	30 नवम्बर, 2015
■ किलकरी योजना	25 दिसम्बर, 2015
■ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	13 जनवरी, 2016
■ स्टार्ट-अप इंडिया	16 जनवरी, 2016
■ सेतु भारतम् परियोजना	4 मार्च, 2016
■ नेशनल रूबन मिशन	21 फरवरी, 2016
■ स्टैण्ड अप इण्डिया	5 अप्रैल, 2016
■ ग्रामोदय से भारत उदय अभियान	14 अप्रैल, 2016
■ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	1 मई, 2016
■ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना	1 जून, 2016
■ स्मार्ट सिटी मिशन	25 जून, 2016
■ गैस 4 इण्डिया	6 सितम्बर, 2016
■ उड़ान योजना (UDAN)	21 अक्टूबर, 2016
■ सौर सुजला योजना	1 नवम्बर, 2016
■ प्रधानमंत्री युवा योजना	9 नवम्बर, 2016
■ भीम एप (BHIM)	30 दिसम्बर, 2016
■ प्रवासी कौशल विकास योजना	7 जनवरी, 2017
■ वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)	24 जनवरी, 2017
■ राष्ट्रीय वयोश्री योजना	1 अप्रैल, 2017
■ भारतनेट परियोजना फेज - 2	19 जुलाई, 2017
■ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	21 जुलाई, 2017
■ आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)	21 अगस्त, 2017
■ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य'	25 सितम्बर, 2017
■ 'साथी' अभियान (SAATHI)	24 अक्टूबर, 2017
■ दीनदयाल 'स्पर्श' योजना (SPARSH)	3 नवम्बर, 2017
■ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB)	1 सितम्बर, 2018
■ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत	23 सितम्बर, 2018
■ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	5 मार्च, 2019
■ फिट इंडिया मूवमेंट	29 अगस्त, 2019
■ प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना	12 सितम्बर, 2019